

14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक
मो0 : 9319040869

दिनांक : 15-9-2017

पत्रांक : 14/शासन/2017
सेवा में,

श्री घनश्याम मीना
अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.)
भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राम कुमार अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

संदर्भ- आपके कार्यालय की प.सं. फ.स.आई.-1-34014/194/2017- आर.टी.आई. दिनांक 05/09/2017

महोदय,
आपका 5/9/2017 का पत्र मुझे 12-9-2017 को प्राप्त हुआ। आपके उपरोक्त पत्र के अनुपालन में I.P.O. No. 33F 872845 रु. 10/- संलग्न है। मेरे पूर्व पत्र सं. 12/शासन/2017 दिनांक 24/08/2017 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए निवेदन है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

14, नन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक

मो० : 9319040869

प.सं. 12/2017/शासन

दिनांक : 24-8-2017

पत्रिका सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय
नई दिल्ली।

विषय: एन०एच० - 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी०बी०आई० से कराने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

सन्दर्भ- मेरी प०सं० 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 ।

महोदय,

कृपया मेरे संदर्भित पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। एन.एच.- 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा की गई थी। माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री, नई दिल्ली द्वारा C.B.I. जांच न कराकर, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हतोत्साहित किया गया था। इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया था परन्तु आज तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 (फोटोकॉपी संलग्न) का कहना है एन.एच. घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में गई।

निवेदन है कि घोटाले की जांच के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का

कष्ट करें-

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून की सिफारिश के अनुसार N.H. 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. द्वारा कराई जायेगी या नहीं?
2. यदि कराई जानी है तो कब तक शुरू होगी ?
3. अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 के अंक में छपा है कि "माना जा रहा है कि घोटाले की जद में आ रहे अफसरों और नेताओं के दबाव के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।" इसमें कितनी सच्चाई है।

सूचना के लिए आवश्यक शुल्क रु० 10/- I.P.O. No. 33F 872844 के रूप में संलग्न है।

संलग्नक- तीन

राम कुमार
(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

14. गन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल
वरिष्ठ नागरिक

मो0 : 9319040869

प.सं. 12/2017/शासन

दिनांक : 24-8-2017

पत्रांक सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय
नई दिल्ली।

विषय: एन0एच0 - 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के सम्बन्ध में सूचना के अधिकार 2005 के अर्न्तत सूचना उपलब्ध कराना।

सन्दर्भ- मेरी प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 ।

महोदय,

कृपया मेरे संदर्भित पत्र का संदर्भ लेने का कष्ट करें। एन.एच.- 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. से कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा की गई थी। माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री, नई दिल्ली द्वारा C.B.I. जांच न कराकर, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हतोत्साहित किया गया था। इस सम्बन्ध में उपरोक्त पत्र द्वारा माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया था परन्तु आज तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 (फोटोकॉपी संलग्न) का कहना है एन.एच. घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में गई।

निवेदन है कि घोटाले की जांच के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का

कष्ट करें-

1. माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड प्रदेश, देहरादून की सिफारिश के अनुसार N.H. 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच C.B.I. द्वारा कराई जायेगी या नहीं?
2. यदि कराई जानी है तो कब तक शुरू होगी ?
3. अमर उजाला दिनांक 19/08/2017 के अंक में छपा है कि 'माना जा रहा है कि घोटाले की जद में आ रहे अफसरों और नेताओं के दबाव के चलते मामला ठंडे बस्तों में चला गया है।' इसमें कितनी सच्चाई है।

सूचना के लिए आवश्यक शुल्क रु0 10/- L.P.O. No. 33F 872844 के रूप में संलग्न

है।

संलग्नक- तीन

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपि श्री नरेन्द्र दास मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7, रेसकोर्स, नई दिल्ली को प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। उक्त पत्र द्वारा जानना चाहा था कि क्या माननीय गडकरी जी का पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम है। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। प्रतीत होता है कि मामले की C.B.I. जांच न कराने में आपकी मौन स्वीकृति है। क्या इसी प्रकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ा जा सकेगा ?

सादर

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, श्री अभित शाह जी, 11 अशोक मार्ग, नई दिल्ली को प0सं0 04/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। उक्त पत्र द्वारा जानना चाहा था कि इस मामले में पार्टी के क्या दिशा-निर्देश हैं। क्या घोटालों पर पर्दा डालकर 350 + का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। कृपया अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपि श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून को प0सं0 01/2017/शासन दिनांक 27/05/2017 के तारतम्य में प्रेषित। आपके द्वारा NH - 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की गई थी। जिस पर माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी द्वारा आपको पत्र लिखकर कहा गया था कि "इस प्रकार के फँसलों से सरकारी अधिकारियों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। सरकार के

इस फैसले से पैदा हुए माहौल में उत्तराखण्ड में और अधिक परियोजनाओं को लाने के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा।”

कृपया माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री के उपरोक्त पत्र की एक छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 12/2017/शासन

दिनांक 24/08/2017

प्रतिलिपि श्री वैभव डांगे, निजी सचिव, सड़क परिवहन राजमार्ग एवं पोत परिवहन मन्त्री, भारत सरकार (Room No. 503, Transport Bhawan, 1, Sansad Marg, New Delhi - 110001) को उनके D.O. 1236499/MIN/RT & H / VIP / 2017 Dated 06/06/2017 के संदर्भ में प्रेषित। आपका 6 जून, 2017 का पत्र दिनांक 11/07/2017 को एक माह से भी ज्यादा समय में प्राप्त हुआ। दिल्ली से हरिद्वार तक आने में पत्र को 35 दिन का समय लग गया इसी से सड़क परिवहन के निर्माण कार्यों की गति का पता चलता है। आपके उक्त पत्र से ज्ञात हुआ कि मेरा 27/05/2017 का पत्र संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय को भेज दिया गया है। परन्तु इससे यह पता नहीं चलता कि CBI जांच होगी या नहीं। संयुक्त सचिव से अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया प्रकरण को पुनः संज्ञान में लेने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

(राम कुमार अग्रवाल)
वरिष्ठ नागरिक

अमर उजाला - देहशून

दिनांक 19-8-2017

Page-6

31/8/2017
19-8-2017

एनएच का घोटाला संसद में उठाने की मांग

हरिद्वार (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन्त्रिमण्डल में एनएच का घोटाला उठाने की मांग को लेकर संसद में उठाने की मांग की है। एनएच-74 में करोड़ों के घोटाले को ध्यान में रखते हुए सरकार इस में तीव्रता से जांच कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।

Page-13

ठंडे बस्ते में गई एनएच घोटाले की जांच

हरिद्वार (ब्यूरो)। एनएच-74 घोटाले की जांच को सीबीआई की नजर में रखते हुए सरकार ने जांच को तेज करने का फैसला किया है। एनएच-74 घोटाले की जांच को तेज करने के लिए सरकार ने जांच को तेज करने का फैसला किया है। एनएच-74 घोटाले की जांच को तेज करने के लिए सरकार ने जांच को तेज करने का फैसला किया है। एनएच-74 घोटाले की जांच को तेज करने के लिए सरकार ने जांच को तेज करने का फैसला किया है।

अमर उजाला 19-8-17

14, गन्दपुरी कॉलोनी, निकट आर्यनगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार 249407 (उत्तराखण्ड)

राम कुमार अग्रवाल

वरिष्ठ नागरिक

मो0 : 9319040869

पत्रांक :

दिनांक :

प.सं. 01/2017/शासन

दिनांक: 27-05-2017

सेवा में,

माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री
श्री नितिन गडकरी जी
नई दिल्ली।

विषय: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एन.एच-74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी.बी.आई.
से कराने की सिफारिश।

मान्यवर,

उत्तराखण्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने एन.
एच.- 74 के भूमि अधिग्रहण घोटाले की जांच सी.बी.आई. से कराने की सिफारिश की थी। सी.
बी.आई. द्वारा जांच शुरू न करने पर दो रिमाइंडर भी भेजे गए।

दिनांक 23 मई 2017 के 'अमर उजाला' समाचार पत्र से पता चला कि आपने मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड को पत्र लिखकर इस मामले में दर्ज FIR & CBI जांच के फैसले पर चिंता जताई
है। आपका कहना है कि "इस प्रकार के फैसलों से सरकारी अधिकारियों के मनोबल पर
विपरीत असर पड़ता है" इतना ही नहीं आपने चेतावनी भी दे डाली "सरकार के इस फैसले
से पैदा हुए माहौल में उत्तराखण्ड में और अधिक परियोजनाओं को लाने के बारे में
पुनर्विचार करना पड़ेगा।" आपका यह तर्क, वितर्क है।

आपका इस प्रकार का पत्र राज्य सरकार को लिखना बहुत ही निराशजनक और
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। स्पष्ट है कि आप नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे
और बेईमान कर्मचारियों / अधिकारियों को दंडित किया जावे। आपके पत्र से बेईमान लोगों
के हौंसले बुलन्द होंगे, अब अन्य राज्य सरकारें भी CBI जांच की बात नहीं करेंगी। फलस्वरूप
भ्रष्टाचार दिन दूना सत चौगुनी उन्नति करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की Zero Tolerance of
'Corruption' की बात भी बेमानी हो जायेगी।

राजा को विवेकशील, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होना ही चाहिए।

आपके पत्र से प्रतीत होता है कि कुमाऊँ क्षेत्र के दो प्रमुख भाजपा नेताओं की घोटाले में
लिप्यता (अमर उजाला 23-05-2017 के अनुसार) होने और उन्हें बचाने की चेष्टा है। आप
चाहते हैं खाओ खिलाओ और मजा करो।

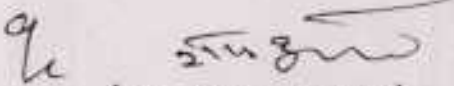
दिनांक 10-7-2017 को सी.बी.आई. 249, काथेजाला क्रमशः 2 पर
द्वारा पारोवहन गैरमा लय 4 नो. 4-40 पर वाती लय

"जब जब होइ धरम के हानी।
बाढहि असुर अधम अभिमानी।।"

इस पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य ही अवगत कराने का कष्ट करेंगे मैं ऐसी आशा करता हूँ। समाचार पत्र का कटिंग संलग्न है।

सादर।

संलग्नक- यथोक्त

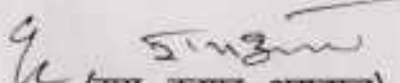

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं0 01/2017/शासन

दिनांक: 27-05-2017

प्रतिलिपि श्री नरेन्द्र दास मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 7, रेसकोर्स नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया विषयक प्रकरण को संज्ञान में लेने की कृपा करें। कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें कि क्या गडकरी जी का इस प्रकार का राज्य सरकार पर दबाव बनाना उचित है। आपने जनता के बीच में कई बार घोषणा की है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिन उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है उसमें देश की तरक्की, ईमानदारी पक्की शीर्षक में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े कदम उठाने की बात कही गई है। क्या गडकरी जी का पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम है। कृपया इस सम्बन्ध में अपने विचारों से अवगत कराने का कष्ट करें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपकी मौन स्वीकृति है।

सादर।

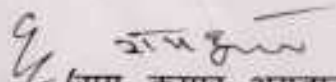

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं 01/2017/शासन

दिनांक: 27-05-2017

प्रतिलिपि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी श्री अमित शाह जी 11 अशोक मार्ग नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया वे भी प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए स्पष्ट करने का कष्ट करें कि इस सम्बन्ध में पार्टी के क्या दिशा-निर्देश हैं।

सादर।


(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं ०1/2017/शास

दिनांक: 27-05-2017

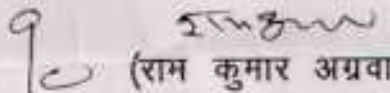
प्रतिलिपि श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार सचिवालय सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित। आपके सामने इस समय बड़ी विकट स्थिति है। न्याय संगत कदम उठाने में आपको पहले ही दिल पर पत्थर रखना पडा था अर्थात् न चाहते हुए भी CBI जांच के लिए सिफारिश करनी पड़ी थी। अब गडकरी जी के पत्र ने आपके सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर दी है। अब इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए आपको श्री कृष्ण जैसे सारथी की आवश्यकता है।

"Make it rule of life never to regret and never to look back. Regret is an appalling waste of energy. You can't build on it, it's only for wallowing."

Mansfield

परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाने के लिए मन:स्थिति को मजबूत करना आवश्यक है। जो सफलता की कुंजी है। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।

सादर।

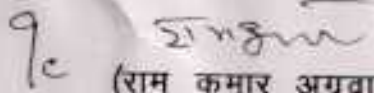

(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

प0सं ०1/2017/शासन

दिनांक: 27-05-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित समचार पत्रों को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले समाचार संजीदगी के साथ उजागर करने का प्रयास निरन्तर बना रहे।

1. अमर उजाला, हरिद्वार- देहरादून
2. दैनिक जागरण, हरिद्वार - देहरादून
3. हिन्दुस्तान, हरिद्वार - दिल्ली
4. राष्ट्रीय सहारा - हरिद्वार
5. नवभारत टाइम्स - दिल्ली
6. Hindustan Times - Delhi
7. Times of India - Delhi


(राम कुमार अग्रवाल)
भारतीय वरिष्ठ नागरिक

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
TRANSPORT BHAVAN, 1 PARLIAMENT STREET
NEW DELHI - 110001

Receipt No. 5261

Dated 20/9/12

Received RTI Application dated.....

from Sh. Smt. / Mr. Ram Kumar

along with application fee of Rs. 10/- (Rupees Ten
only) / Fee of Rs. _____ (Rupees _____)

only) for providing information under RTI Act 2005 in

Cash / Demand Draft / Cheque / IPO No. 33 F 879845

Dated



Signature / Receipt Official (IFC)

फ.स.आई-1-34014/194/2017-आरटीआई

भारत सरकार
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

दिनांक- 05.09.2017

सेवा में,

श्री राम कुमार अग्रवाल
14, नन्दपुरी कॉलोनी
निकट आर्यनगर चौक
जवाला हरिद्वार - 249407
(उत्तराखण्ड)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राम कुमार अग्रवाल से प्राप्त आवेदन।

महोदय,

मुझे आपका पत्र दिनांक 24.08.2017 जो की इस मंत्रालय में दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ का अवलोकन करने का निर्देश हुआ है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कतिपय सूचना मांगे जाने के संबंध में है।

2. इस संबंध में यह देखा गया है कि आपके द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के पक्ष में अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया है। अतः आपसे अनुरोध है कि 'भुगतान एवं लेखा अधिकारी (सचिवालय)' सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, को देय 10 ₹0 का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ भारतीय पोस्टल आर्डर इस मंत्रालय को तुरंत भेजा जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पर कारवाई 'आवेदन शुल्क' जमा कराने का बाद ही की जा सकती है। 10 ₹0 का IPO 33F 872844 इसके साथ वापस किया जा रहे हैं।

all

भवदीय

धनश्याम मीना

घनश्याम मीना

अनुभाग अधिकारी(आर.टी.आई)

